

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 02 ^{जुलै} अक्टूबर, 2020

विषय:-प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासकीय अधिसूचना संख्या-36/XXXVI(3)/2014/11(1)/2014, दिनांक 27-01-2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत वर्ग-4 की ऐसी भूमि जिस पर व्यक्ति दिनांक 30.06.1983 अथवा उससे पूर्व अनाधिकृत रूप से काबिज थे तथा सम्प्रति इस भूमि पर काबिज है, पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रसार किया गया है, साथ ही ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये हैं, के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-804/XVIII(II)/2016-07(46)/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2016 द्वारा सिद्धान्त एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं।

2- उपरोक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश संख्या-804/XVIII(II)/2016-07(46)/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2016, शासनादेश संख्या-301/XVIII(II)/2018-07(46)/2008 दिनांक 19 फरवरी, 2018 तथा शासनादेश संख्या-293/XVIII(II)/2019-07(46)/2008 दिनांक 26 फरवरी, 2019 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय शासकीय अधिसूचना संख्या-36/XXXVI(3)/2014/11(1)/2014, दिनांक 27-01-2014 से आच्छादित ऐसे व्यक्ति जो वर्ग-4 की भूमि पर दिनांक 30.06.1983 अथवा उससे पूर्व अनाधिकृत रूप से काबिज थे एवं सम्प्रति काबिज हैं को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधनों/शर्तों के साथ जनपद के जिलाधिकारियों को अधिकृत करते हुए सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) यह शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा।
- (2) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दरों पर वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किया जायेगा:-

(क) 100 वर्ग मीटर तक की भूमि के विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2004 के सर्किल रेट का 05

प्रतिशत लिया जायेगा।

- (ख) 101 से 200 वर्ग मीटर तक की भूमि के विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2004 का सर्किल रेट लिया जायेगा।
- (ग) 201 से 400 वर्ग मीटर तक की भूमि के विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2004 के सर्किल रेट से 10 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।
- (घ) 401 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि का विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2004 के सर्किल रेट से 25 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।
- (2) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे:-जलमग्न, चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चारागाह या ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के प्रयोग में आती हो) का विनियमितीकरण नहीं किया जायेगा। इन भूमियों के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, मा0 उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (पी0आई0एल0) 65/2011 कुंवर पाल सिंह एवं अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांकित 13-06-2018 एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चारागाह आदि) पर यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे पहले खाली कराया जायेगा और तब उस अध्यासी/पट्टेदार की अवशेष अन्य वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण किया जायेगा।
- (4) अध्यासी/पट्टेदार की वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण करने से पूर्व तहसीलदार को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि जिस व्यक्ति के अवैध कब्जे की भूमि विनियमित की जा रही है, उस व्यक्ति के पास धारा-132 के अधीन आने वाली भूमि अवैध कब्जे में नहीं है।
- (5) वर्ग-04 की उस भूमि का विनियमितीकरण, जिसका वाद मा0 न्यायालय में लम्बित है, इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि विनियमितीकरण मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।
- (6) वर्ग-04 की भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम एवं वन संरक्षण से सम्बन्धित अन्य प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) वर्ग-04 की भूमि पर पट्टेदारों को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने हेतु पट्टेदार द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि को वर्तमान में विनियमितीकरण हेतु निर्धारित धनराशि में समायोजित किया जायेगा।
- (8) वर्ग-04 की भूमि के 3.125 एकड़ से अधिक भूमि के विनियमितीकरण के प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जायेंगे।
- (9) विनियमितीकरण हेतु पात्र अध्यासियों/पट्टेदारों की पहचान उनका नाम खतौनी के श्रेणी-04

में अंकित अभिलेख से ही किया जायेगा। खतौनी में अंकित व्यक्ति के ऐसे भूमि पर कब्जे का सत्यापन तहसील स्तर पर ही किया जायेगा तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

- (10) वर्ग-04 के ऐसे अध्यासी/पट्टेधारक, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वैधानिक वारिसान के पक्ष में अभिलेखीय पुष्टि करने के पश्चात विनियमितीकरण कर लिया जाये, कि जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम, 1950 में उपबन्धित व्यवस्था के अनुसार मृतक अध्यासी/पट्टेधारक के उत्तराधिकारी प्रश्नगत भूमि पर काबिज है।
- (11) खतौनी के वर्ग-04 के ऐसे खातों में जहां अनाधिकृत अध्यासियों/पट्टेदारों का नाम संयुक्त रूप से अंकित है और उनमें, भिन्न-भिन्न परिवारों के व्यक्ति भी शामिल हैं, ऐसे मामलों में यदि किसी डीड के आधार पर संयुक्त अध्यासी/पट्टेधारकों के हिस्से भिन्न-भिन्न हैं, तो उसी के अनुसार विनियमितीकरण किया जाये, अन्यथा उनके हिस्से बराबर मानकर कार्यवाही की जाय। यह ध्यान रखा जाये कि संयुक्त कब्जे की भूमि उपरोक्तानुसार पट्टे पर दिये जाने से किसी व्यक्ति के परिवार के पास विनियमितीकरण के उपरान्त सीलिंग सीमा से अधिक भूमि न होने पाये।
- (12) प्रश्नगत भूमि पर अनाधिकृत काबिज/पट्टेधारक, जो व्यक्ति शासनादेश की 01 वर्ष की अवधि में उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर विनियमितीकरण नहीं करायेगे, उनके विरुद्ध राज्य सरकार में भूमि निहित किये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (13) जिन मामलों में विधिक कठिनाईयां होंगी या अन्य दावेदारों द्वारा भी विनियमितीकरण का अनुरोध इस आधार पर किया जायेगा कि वे उपरोक्त श्रेणियों में है/इन श्रेणियों के समकक्ष है, ऐसे सभी प्रकरणों को परीक्षण के लिये शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (14) उपरोक्त कार्यवाही के लिए जिले के जिलाधिकारी द्वारा वर्ग-4 के अनाधिकृत कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी के अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा भूमि विनियमितीकरण हेतु जिलाधिकारी के द्वारा अभियान चलाकर तथा स्वयं मासिक समीक्षा की जायेगी तथा विनियमितीकरण हेतु विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।
- (15) भारत सरकार के प्रतिष्ठानों को शासनादेश संख्या-258/16(1)73 राजस्व-1 दिनांक 09.05.1984 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-496/XVIII(II)/2020-08(63)2016 दिनांक 28.07.2020 की शर्तों के अधीन भूमि सःशुल्क दी जायेगी तथा राज्य सरकार के विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी।
- (16) उक्त सभी मामलों में विनियमितीकरण की प्रक्रिया समयबद्ध आधार पर पूर्ण करने तथा उपरोक्त पात्रता का अनुपालन करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तरदायी होंगे तथा उनके द्वारा मासिक आधार पर इस प्रक्रिया का अनुश्रवण भी किया जायेगा, जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र पर राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी शासन स्तर पर भी मासिक समीक्षा की जायेगी।

3— प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के पट्टों के विनियमितीकरण एवं अवैध कब्जों को विनियमितीकरण हेतु प्राप्त भू-राजस्व शुल्क/नजराने की धनराशि को राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत

लेखा— शीर्षक-0029-भू-राजस्व-00-101 भू-राजस्व/कर-02 सरकारी आस्थानों से उगाहियों-किसानों से लगान-09 प्रकीर्ण के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा।

4— अतः प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

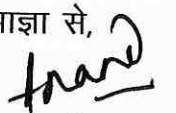
(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-958/XVIII(II)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4— प्रमुख निजी सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
- 5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7— आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 8— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
- 9— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(डॉ आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।